

ग्रीन हाइड्रोजन

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

एक नई रपौर्ट ने भारत को हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक संभावित वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जिसके पास वर्ष 2030 तक वैश्विक बाजार का 10% हिस्सा प्राप्त करने और प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन निर्यात करने की क्षमता है।

ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) क्या है?

- **परिचय:** ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं (H_2O) को हाइड्रोजन (H_2) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है।
 - इसे बायोमास गैसीफिकेशन की प्रक्रिया से भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें बायोमास को हाइड्रोजन-समृद्ध गैस में परिवर्तित किया जाता है।
- **अनुप्रयोग:** इसके उपयोगों में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV), विमानन एवं समुद्री परिवहन, उर्वरक, रफाइनरी और इस्पात जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।
 - इसका उपयोग सड़क और रेल परिवहन, नौवहन (Shipping) तथा विद्युत उत्पादन में भी संभावित है।
- **भारत की ग्रीन हाइड्रोजन महत्वाकांक्षाएँ:** राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (Certification Scheme) तथा कांडला, पारादीप और तूतीकोरनि में ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास जैसी नीतियों के माध्यम से भारत अपनी ग्रीन हाइड्रोजन महत्वाकांक्षाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है (MAPS):
 - **M – Market Leadership (बाजार में नेतृत्व):** वर्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) बाजार का 10% हिस्सा प्राप्त करना, जो 100 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से अधिक होने का अनुमान है।
 - **A – Abatement of Emissions (उत्सर्जन में कमी):** प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT CO_2 की कमी सुनिश्चित करना, जो भारत की NDC एवं नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप है।
 - **P – Powering Production (उत्पादन को प्रोत्साहन):** वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना।
 - **E – Employment Creation (रोजगार सृजन):** अनुसंधान एवं विकास से लेकर उत्पादन, भंडारण और निर्यात तक, GH2 मूल्य शृंखला में 6 लाख से अधिक हरित नौकरियाँ उत्पन्न करना।

हाइड्रोजन के अन्य प्रकार:



भारत की ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रगति **CAGE** के कारण बाधित है, जो इसके वसतिार की क्षमता को सीमित करता है:
- **C – Cost Barrier (लागत बाधा):** शुरुआती चरण में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत लगभग **4–4.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम** है, जो ग्रे हाइड्रोजन से कहीं अधिक है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा कठिन हो जाती है।
- **A – Access to Capital (पूँजी तक पहुँच):** इलेक्ट्रोलाइज़र और नवीकरणीय क्षमता में भारी अग्रिम निवेश की आवश्यकता नज़ी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं को हतोत्साहित करती है।
- **G – Gaps in Infrastructure (अवसंरचना की खामियाँ):** परिवहन पाइपलाइन, भंडारण और रीफ्यूलिंग नेटवर्क की कमी के कारण इसे अपनाने में देरी हुई।
- **E – Economic Viability Issues (आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी समस्याएँ):** कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र में देरी के कारण जीवाश्म ईंधन-आधारित हाइड्रोजन कृत्रिम रूप से सस्ती बनी रहती है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रतिस्पर्द्धा कमज़ोर होती है।

ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने हेतु भारत कौन-से उपाय अपना सकता है?

- **CAGE** की बाधाओं को दूर करने के लिये भारत को **POWER** रणनीति अपनानी होगी।
- **P – Pricing Carbon (कार्बन मूल्य निर्धारण):** कार्बन टैक्स/बाज़ार तंत्र को शीघ्र लागू करना, ताकि जीवाश्म ईंधनों के साथ समान प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की जा सके।
- **O – Obligation Mandates (अनिवार्य दायित्व):** कठिन क्षेत्रों (इस्पात, उर्वरक, शोधन) में हरित हाइड्रोजन खरीद दायित्वों को लागू करना।
- **W – Widen Infrastructure Base (अवसंरचना का वसतिार):** यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे साझेदारों के साथ इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता, भंडारण, परिवहन पाइपलाइन और निर्यात गलियारों का निर्माण करना।
- **E – Economic Reallocation (आर्थिक पुनःआवंटन):** जीवाश्म ईंधनों से सबसिडी हटाकर ग्रीन हाइड्रोजन को देना, साथ ही कर प्रोत्साहन एवं व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (**Viability Gap Funding**) प्रदान करना।
- **R – Risk Pooling through Demand Aggregation (मांग समेकन द्वारा जोखिम साझा करना):** भुगतान सुरक्षा तंत्रों के साथ संयुक्त खरीद प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि विश्वसनीय अनुबंध और प्रतिस्पर्द्धा मूल्य सुनिश्चित किये जा सकें।

मेन्स के लिये की-वरड्स

- “हाइड्रोजन इज़ द न्यू आयल” – भविष्य का ईंधन।
- “एकट ग्रीन, ट्रेड ग्रीन” – सतत् विकास हेतु निर्यात गलियारे।
- “सस्टेनेबिलिटी इज़ द टुरएस्ट धर्म” – हरित ऊर्जा नैतिक ज़िम्मेदारी के रूप में।
- “ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ नयित्व के साथ भारत का एक प्रयास है।”



राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission-NGHM)

नोडल मंत्रालय

- ▶ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

NGHM के घटक

- ▶ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिये रणनीतिक क्रियाकलाप (SIGHT)
- ▶ रणनीतिक हाइड्रोजन नवाचार भागीदारी (SHIP) (अनुसंधान एवं विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी)

GH2 वर्तमान में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है; भारत में वर्तमान लागत लगभग 350-400/किग्रा है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन का लक्ष्य इसे 100/किग्रा के नीचे लाना है।

उद्देश्य

- ▶ ऊर्जा/उद्योग/मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज (कार्बन मुक्त) करना
- ▶ स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करना
- ▶ GH2 और इसके व्युत्पन्नों के लिये निर्यात के अवसर सृजित करना

वर्ष 2030 तक अपेक्षित परिणाम

- ◆ प्रति वर्ष कम-से-कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) हरित हाइड्रोजन (GH2) का उत्पादन
- ◆ जीवाश्म ईंधन के आयात में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत
- ◆ छह लाख से अधिक रोजगार
- ◆ वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी
- ◆ ₹ 8 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश

हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन

- ◆ हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है लेकिन यह अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों (जैसे जल) से अलग किया जाता है।
- ◆ अक्षय/नवीकरणीय ऊर्जा (RE) द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी/इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस/विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) बनाया जाता है।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/green-hydrogen-32>

